![VISIONIAS logo]

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0792327

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Anju

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
हिंदी

तारीख
Date
28 Aug, 2022

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)
GENERAL STUDIES (Paper III)

केंद्र
Centre
जयपुर

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

VISION IAS

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISIONIAS

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ-साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Fiscal policy can be a key tool to reduce income inequality as well as make the poorest and the downtrodden a part of the country's growth story. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर - हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022

→ भारत में (1%) आबादी के पास कुल राष्ट्रीय GDP की लगभग (22%) संपत्ति संचित है

→ (50%) आबादी के पास = (13%)

अतः आय असमानता एवं निर्धन तथा अभावग्रस्त लोगों को राष्ट्रीय विकास यात्रा में शामिल करने हेतु राजकोषीय नीति की प्रासंगिकता

→ (i) भारत में प्रत्यक्ष कराधान में सुधार द्वारा

→ (ii) सुपररिच पर टैक्स (प्रत्यक्ष) में वृद्धि

→ (iii) बिग टेक्नो कार्म्स पर प्रत्यक्ष कर वसूली को बढ़ावा

→ (iv) व्यवहारिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत द्वारा कर अदायगी हेतु प्रोत्साहन

(vi) GST (वस्तु एवं सेवा कर) मे सुधार जरूरी
→ चूँकि इसका सर्वाधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ता है।

(vii) अत्याधिक गरीब आबादी की क्रयशक्ति एवं खपत में वृद्धि हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा

उपर्युक्त आधार पर आय का समाज में पुनःवितरण संभव होगा। जिससे निर्धन आबादी भी आर्थिक क्रियाओं मे भागीदारी निभा सकेगी। साथ ही सतत विकास लक्ष्य - 10.0 (रिड्यूस इनइक्वैलिटी) एवं (DPSP) नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद - 38 (आय असमानता को समाप्त करना) के लक्ष्य की भी प्राप्ति संभव होगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना भूमि सुधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी काफी सहायक होगा। विस्तारपूर्वक समझाइए। साथ ही, इस संदर्भ में किए गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Digitizing land records will go a long way in ensuring land reforms as well as lessening the burden on the Indian Judiciary. Elaborate. Also, state the measures taken in this context. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर- वर्तमान संदर्भ में भूमि सुधारों में सर्वाधिक आवश्यकता भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण है।

(*) भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लाभ

(i) किसानों को संस्थागत ऋणों तक पहुंच तय करना

(ii) भू स्वामित्व संबंधी मुद्दों का बेहतर निपटान (न्यायिक बोझ में कमी)

(iii) लैण्ड लीजिंग आसान

(iv) भूमि की उत्पादकता में वृद्धि (भूमि संबंधी सही आकलन के कारण उचित कृषि इनपुट देना आसान होगा)

(*) औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन

(i) लैण्ड लीजिंग आसान → औद्योगिक कारखाने गठित → रोजगार का सृजन → आर्थिक विकास

* भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

(i) स्वामित्व योजना →
- ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर ढंग से आकलन एवं ई संपत्ति कार्डों का वितरण

(ii) किसान ड्रोन – बजट-2022-23 में किसान ड्रोन्स की घोषणा की गई

भूमि का बेहतर आकलन | भू आभिलेखों का डिजिटलीकरण | बेहतर कृषि इनपुटस

(iii) मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट
→ भूमि आभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं लैण्ड लीजिंग को आसान बनाना।

(iv) भूमि बैंक कंपनी

वस्तुतः उपर्युक्त सभी ~~पहली~~ पहले वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन-मेरिट सब्सिडी के लिए निधि (फंड) उपलब्ध कराने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति, भारत में कुछ राज्यों को गंभीर राजकोषीय संकट के कगार पर धकेल रही है। इस संदर्भ में, भारत में सब्सिडी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
It has been pointed out that competitive politics to fund mostly non-merit subsidies is pushing a few states in India to the brink of a deep fiscal crisis. In this context, discuss the need to rationalise the subsidy regime in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर - वर्तमान संदर्भ में नॉन मेरिट सब्सिडी (जैसे फ्रीबीज) के रूप में भी देखा जा रहा है, (चिंता का प्रमुख कारण बनी हुई है।

(A) नॉन मेरिट सब्सिडीज के परिणाम

(i) राज्यों के ऋण-GDP अनुपात में असंतुलित वृद्धि
यथा - पंजाब-हरियाणा में (एन. के सिंह कमेटी) की सिफारिशों से भी अधिक ऋण-GDP अनुपात हो गया है।

(ii) विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी के चलते किसानों द्वारा असंधारणीय कृषि सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कृषि भूमि हेतु अनुचित है।

(iii) विद्युत सब्सिडी के परिणाम
- जल का अति दोहन
- डिस्कॉम्स को घाटा

* साब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने हेतु उपाय

(i) टारगेटेड साब्सिडी को बढ़ावा
यथा - बच्चो को शिक्षा दिए जाने पर साब्सिड़ी का प्रस्ताव

(ii) आर्थिक धनी किसानों को साब्सिडी में कटौती

(iii) सोलर पैनल (खेतों में) लगवाने हेतु प्रेरित करना

वस्तुत: साब्सिडी का युक्तिसंगीतिकरण वर्तमान की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. सूक्ष्म-सिंचाई में कृषि को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में परिवर्तित करने की वृहद् क्षमता है। दिए गए कथन की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Micro-irrigation has tremendous potential in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Discuss the given statement in the context of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर- भारत में अधिकांश भौमजल एवं धरातलीय जल (लगभग 89%) का उपभोग कृषि सिंचाई हेतु प्रयुक्त हो रहा है।

* सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकता क्यों?

→ (i) भूमिगत जल के धारणीय प्रयोग हेतु
→ (ii) अति सिंचाई से कृषि भूमि की उत्पादकता में गिरावट (लवणीकरण में वृद्धि)
→ (iii) सतत एवं धारणीय कृषि के प्रोत्साहन हेतु
→ (iv) बेहतर एवं प्रभावी उत्पादन हेतु

* प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

→ वस्तुतः कृषि सिंचाई प्रणाली को अधिक युक्तिसंगत बनाने एवं संधारणीय कृषि विकास हेतु चलाई गई योजना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक

(i) वाटरशेड प्रोग्राम

(ii) पर ड्रॉप मोर क्रॉप

(iii) बूँद - बूँद जल सिंचाई प्रणाली का विकास

(iv) जल के संधारणीय उपभोग हेतु जन जागरूकता

(v) कम सिंचित क्षेत्रों तक सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा

वस्तुतः सूक्ष्म सिंचाई योजना ने इजरायल जैसे कम जल उपलब्धता वाले देश को भी समृद्ध बना दिया है। अतः वर्तमान संदर्भ में जल से एवं कृषि भूमि से जुड़ी अनेकों समस्याओं के समाधान में यह सहायक हो सकती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. भारत के विशाल संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपीय देशों (PSIDS) की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Given its vast resources and technical expertise, India can play a key role in assisting the Pacific Small Island Developing States (PSIDS) in dealing with the impact of climate change. Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर- IPCC की VI आकलन रिपोर्ट मे बढ़ते तापमान के चलते समुद्री जल स्तर मे वृद्धि की संभावना व्यक्त की है।

वस्तुत: समुद्री जलस्तर मे वृद्धि से लघु द्वीपीय देश सर्वाधिक प्रभावित होंगे।

(*) लघु द्वीपीय देशों की सहायता हेतु भारत सरकार की पहल

→ (i) कॉप-26 मे 'IRIS' पहल। जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति द्वीपीय देशों को अधिक लचीला (Resilient) बनाना।

→ (ii) वैश्विक स्तर पर 'CDRI' का उद्देश्य भी द्वीपीय देशों मे जलवायु परिवर्तन अनुकूल अवसंरचना का निर्माण करना है।

→ (iii) जलवायु न्याय की संकल्पना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

— यद्यपि भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ ही अन्य महासागरीय लघु द्वीपीय देशों की सहायता हेतु आह्वान किया है।

→ तथापि भारत के सम्मुख अभी भी निम्नलिखित चुनौतियाँ व्याप्त है

(i) अपर्याप्त पूँजी
(तथापि भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है)

(ii) तकनीकी का अभाव

किन्तु वर्तमान संदर्भ में भारत लघु द्वीपीय देशों की सहायतार्थ विश्व समुदाय को एकजुट करने हेतु प्रयासरत है। साथ ही स्वयं भी अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी कर रहा है। यथा — पेरिस जलवायु समझौता एवं पंचामृत घोषणाएँ।

6. हालिया "पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR)" का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा प्रत्यास्थता विकसित करना है। इस संदर्भ में, इस योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी तर्क की विवेचना कीजिए और इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
The recent "Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj (DMP–MoPR)" aims to develop disaster resilience at the grassroots level. In this context, discuss the rationale behind the formulation of the Plan and highlight its key components. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर- वस्तुत: आपदा से निपटने में परंपरागत पद्धतियाँ सर्वाधिक प्रभावी हो सकती हैं। इसी संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा '<u>आपदा प्रबंधन योजना</u>' की घोषणा की गई।

आपदा प्रबंधन योजना के प्रमुख घटक

(i) स्थानीय स्तर पर आपदा हेतु तैयारी

(ii) मनरेगा श्रमिकों के सहयोग से भावी आपदाओं के प्रति शमन की नीति

(iii) आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना

(iv) स्थानीय लोगों का क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण

(v) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में समन्वय

(क) आपदा प्रबंधन योजना के पक्ष में तर्क।

→ (i) IPCC की VI आकलन रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि संभव

→ (ii) भारत में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सामुदायिक भागीदारी सीमित

→ (iii) सेन्डई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु

→ (iv) एक सतत, धारणीय एवं आपदा लचीला समाज बनाना

वस्तुतः आपदा प्रबंधन योजना वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रतीत होती है। यह आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित कर कई सारी चुनौतियों का समाधान कर सकती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (EDT) के उपयोग से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा संबंधी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the internal security implications emanating from the use of Emerging And Disruptive Technologies (EDT) by state and non-state actors. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर – भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने मे राज्यकर्ता एवं गैर राज्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(क) राज्यकर्ता कारको की भूमिका

(i) राज्य प्रायोजित आतंकवाद
यथा – पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद

(ii) नक्सलवादी घटनाओं को बढ़ावा देने मे बाहरी राज्यो द्वारा वित्त पोषण
यथा – चीन द्वारा, म्यांमार द्वारा उत्तर पूर्व मे फंडिंग एवं हथियारों की सप्लाई

(iii) साईबर अपराधों के जरिये चुनौती उत्पन्न करना
यथा – U.S.A. की एक रिपोर्ट के अनुसार मुम्बई पॉवर सेक्टर पर साइबर हमला चीनी 'रेड इको' एजेंसी द्वारा प्रायोजित है।

② गैर राज्यकर्ता

(i) सोशल मीडिया के माध्यम से हेटस्पीच को बढ़ावा

(ii) कट्टरपंथी संगठनों द्वारा युवाओं को दिग्भ्रमित करना

(iii) अवैध घुसपैठ एवं देश में तस्करी जैसी घटनाओं को प्रोत्साहन

यथा - भारत-म्यांमार, भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर मानव, पशु एवं मादक पदार्थों की तस्करी।

वस्तुतः अवैध गतिविधियों को प्रायोजित करने वाले राज्य अभिकर्ताओं एवं गैर राज्य अभिकर्ताओं से निपटने हेतु एक समग्र रणनीति समय की माँग है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में भारत द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Identify the impediments faced by India in boosting its defence exports. Also, discuss the steps taken by the government in this regard. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर - भारत द्वारा अधिकांश रक्षा सामग्री का बाहर से आयात किया जाता है। जिनमे प्रमुख देश है] रूस > अमेरिका

- भारत दुनिया मे हथियार। रक्षा सामग्री खरीदने वाला II सबसे प्रमुख देश है।

(*) बजट - 2022-23 मे भारत सरकार द्वारा लगभग (68%) रक्षा सामग्री स्वदेशी स्तर पर उत्पादित करने की घोषणा की गई।

(*) भारत के रक्षा निर्यात के सम्मुख बाधाएं

(i) पर्याप्त पूँजी का अभाव
(ii) रक्षा प्रौद्योगिकी मे अपर्याप्त रिसर्च एण्ड डवलपमेंट मे व्यय
(iii) आधुनिक तकनीको हेतु बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता
(iv) स्वदेशी स्तर पर पर्याप्त रक्षा सामग्री नही

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

* आगे की राह

→ (i) निजी - सार्वजनिक भागीदारी द्वारा रक्षा सामग्री के निर्माण हेतु पूँजी जुटाना

→ (ii) नवीन तकनीकों के विकास हेतु 'अनुसंधान की प्रवृत्ति' को बढ़ावा

* भारत सरकार की पहल

→ (i) PLI स्कीम के तहत रक्षा सामग्री के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा

→ (ii) बजट - 2022-23 में एवं वित्त आयोग की सिफारिशों पर रक्षा प्रौद्योगिकी की विकास हेतु व्यय में वृद्धि (बजट बढ़ाया)

वस्तुत: रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता एवं निर्यातउन्मुख शक्ति बनने हेतु भारत को अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। यथा — प्रोजेक्ट - 75I, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक आदि पर फोकस।

9. अंतरिक्ष मलबे से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस खतरे से निपटने के लिए हाल के दिनों में की गई पहलों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the multiple issues associated with space debris. Also, state the initiatives taken in recent times to tackle this menace. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर – अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक गतिविधियों के चलते अंतरिक्ष मलबे की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

→ अंतरिक्ष मलबा क्यों?

→ (i) उपग्रहों की बढ़ती संख्या

→ (ii) भारत के मिशन शक्ति प्रोग्राम जैसे ही अन्य वैश्विक उपग्रह प्रणाली को नष्ट करने वाले कार्यक्रम

→ (iii) निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियाँ

(R) वस्तुतः अंतरिक्ष मलबे हेतु वैश्विक स्तर पर कई संधियाँ पहले की गई हैं।

यथा – (i) बाह्य अंतरिक्ष संधि

→ जिसमें अंतरिक्ष क्षेत्र के धारणीय उपयोग पर बल दिया गया है।

(ii) वर्तमान में अंतरिक्ष मलबे से निपटने हेतु वैश्विक साझेदारी घट बल दिया जा रहा है।

(*) आगे की राह

(i) अंतरिक्ष नैतिकता का अनुपालन

(ii) अंतरिक्ष एक साझी संपत्ति है अतः विभिन्न चुनौतियों से निपटने हेतु साझेदारी जरूरी।

(iii) अंतरिक्ष मलबे से निपटने हेतु नवीन तकनीकों को बढ़ावा

वस्तुतः एक सुरक्षित एवं धारणीय विश्व के लिए अंतरिक्ष मलबे का निपटान आवश्यक है नहीं तो भविष्य में इसके परिणाम प्रतिकूल साबित हो सकते हैं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को अपनाने से उपभोक्ताओं के लिए ई-कॉमर्स के अधिक समावेशी और सुलभ बनने की संभावना है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
The adoption of Open Network for Digital Commerce (ONDC) in India is expected to make e-commerce more inclusive and accessible for consumers. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर – भारत मे ई-कॉमर्स को अधिक युक्तिसंगत बनाने हेतु ई-कॉमर्स संबंधी नए नियम लागू किए गए।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लाभ

(i) उपभोक्ताओ की पारदर्शी ढंग से ई-कॉमर्स तक पहुँच सुनिश्चित करना

(ii) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को उपभोक्ताओ के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना

(iii) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सभी की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना (समावेशन मे वृद्धि)

(iv) गुणवत्ता पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना

(v) वाणित शिकायत निवारण हेतु तंत्र विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्मों को प्रेरित करना

प्रस्तुतः 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स' उपभोक्ता अनुकूल ई-प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. यद्यपि, हाल ही में "क्षतिकारक" सरकारी मत्स्यन सब्सिडी को रोकने के लिए डब्ल्यू. टी. ओ. के मंच पर एक समझौते पर सहमति बनी है, तथापि, भारत द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं से पता चलता है कि इस मामले में और अधिक वार्ता किए जाने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

While an agreement was recently reached at the WTO on a deal to curb "harmful" government fisheries subsidies, certain concerns raised by India suggests that the matter will require further negotiations. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर- हाल में विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कई वैश्विक मुद्दों को संबोधित किया गया गया।

सम्मेलन के विभिन्न निष्कर्ष

(I) वैक्सीन संबंधी ट्रिप्स नियमों में आगामी 5 वर्षों तक छूट

(II) ई-कॉमर्स प्रेषण पर सीमा शुल्क रहित नियमों का आगामी समय तक संचालन

(III) गैरकानूनी, गैर प्रतिवेदित एवं अविनियमित मत्स्ययन (IUU) पर दी जाने वाली हानिकारक सब्सिडी पर आगामी 4 वर्षों हेतु प्रतिबंध

(IV) विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को वैश्विक खाद्य सुरक्षा हेतु निर्यात प्रतिबंधों से छूट

(*) भारत एवं अन्य विकासशील देशों की चिंताएँ :-

(i) मात्र 5 वर्षों तक विकासशील एवं अल्पविकसित राष्ट्रों के लिए सब्सिडी से छूट संबंधी प्रावधान युक्तिसंगत नहीं

(ii) वस्तुत: यह प्रावधान भारत जैसे विकासशील देशों के मत्स्यन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

(iii) चीन द्वारा भारी मात्रा में गैर कानूनी एवं अविनियमित सब्सिडी से मत्स्यन पर विपरीत प्रभाव

(चूँकि चीन स्वयं को विकासशील देशों की श्रेणी का भाग मानता है अत: WTO के ये प्रावधान तार्किक प्रतीत नहीं होते)

* इसीप्रकार WTO के अन्य प्रावधान भी रणनीतिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होते है। यथा :- (i) वैक्सीन निर्माण संबंधी ट्रिप्स नियमों में छूट किन्तु तकनीकी एवं पूँजी हस्तांतरण पर बल नहीं

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

— वस्तुतः उपर्युक्त चिंताओं / मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सम्मेलन के अधिकांश प्रावधान तार्किक नहीं है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. सड़क निर्माण क्षेत्रक में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) से जुड़े लाभों के बावजूद, विभिन्न कारणों से इसमें रुचि कम हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite the advantages that are associated with the hybrid annuity model (HAM) in the road construction sector, the interest in it has moderated due to various reasons. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर - हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, सड़क परिवहन को आर्थिक अनुकूल एवं बेहतर बनाने के दोहरे उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

→ इसके तहत व्यापारिक गतिविधियों को त्वरित करने हेतु सड़क परिवहन का सशक्तिकरण किया जा रहा है।

→ जिसमे विभिन्न प्रकार के अन्य तरीकों का सम्मिश्रण भी किया जा रहा है।

(क) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के लाभ

- (i) सड़कों का मजबूतीकरण
- (ii) बेहतर कनेक्टीविटी को बढ़ावा
- (iii) भविष्य मे त्वरित परिवहन गतिविधियों की संभावना

* अरुचि के कारण

(i) आवश्यकता के अनुरूप सड़कों में सुधार नहीं

(ii) अपर्याप्त अनुसंधान के कारण घटती रुचि

(iii) अत्यधिक पूँजी प्रधान मॉडल

वस्तुत: वर्तमान संदर्भ सड़क परिवहन के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन तकनीकों की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. मौजूदा एम. एस. पी. खरीद व्यवस्था न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही कृषि-पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय है। सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही, मौजूदा एम. एस. पी. व्यवस्था में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The existing MSP procurement regime is neither economically nor agro-ecologically sustainable. Elaborate. Also, evaluate the alternative approaches that can be adopted to improve the existing MSP regime. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर_ मीनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से तात्पर्य बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव की स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य में कृषि उपज की खरीद नीति।

(*) न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ

(i) किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित
(ii) बाजार में उतार-चढ़ाव से किसानों की रक्षा
(iii) किसानों की खरीद (कृषि इनपुट) शक्ति में वृद्धि
(iv) कार्टेलाइजेशन जैसी प्रवृत्तियों के बावजूद किसानों की रक्षा

(*) मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दुष्परिणाम

(I) आर्थिक रूप से असंधारणीय क्यों?

(i) सरकारी राजकोष पर दबाव (राजकोषीय घाटा बढ़ता है)

→ (ii) कृषि विविधीकरण के अभाव में निर्यात बॉस्केट में विविधता नहीं

→ (iii) खाद्यान्न मुद्रास्फीति

[यथा] – खाद्यान्न तेलों से जुड़ी फसलों पर कम फोकस के कारण भारत अपनी जरूरतों का 56-60% खाद्यान्न तेलों का आयात करता है।

→ (iv) भुगतान संतुलन प्रभावित (चालू खाता घाटा बढ़ता है)

(ख) [कृषि एवं पारिस्थितिकीय दृष्टि से असंधारणीय]

→ (i) मोनो क्रॉपिंग को बढ़ावा

[यथा] – गेहूँ – धान पैटर्न पर फोकस

→ (ii) जल निर्भरता फसलों के प्रोत्साहन के कारण भूमिगत जल का ह्रास

→ (iii) धान की कृषि मीथेन (ग्रीन हाउस गैस) के उत्सर्जन में सहायक

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(*) MSP में सुधार हेतु उपाय

→ (i) MSP की बजाय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर बल
[यथा] - ओडिसा की कालिया योजना

→ (ii) किसानों को बिना MSP के मूल्य के ही फसल बिक्री हेतु प्रेरित करना (नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा) — (आर्थिक सर्वे का सुझाव)

(*) वर्तमान सरकार दलहन, तिलहन एवं मोटा अनाज फसलों हेतु MSP पर फोकस है। हाल ही में 'GST काउंसिल' में प्रधानमंत्री ने (MSP) में प्रभावी सुधारों पर बल दिया।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. यह तर्क दिया जा रहा है कि भारत गोदामों में खाद्यान्नों की अधिकता से जूझ रहा है। भारत की मौजूदा बफर स्टॉक नीति को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
It is being argued that India is struggling with overflowing foodgrains in warehouses. Discuss the statement in view of the existing buffer stock policy of India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर - भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बफर स्टॉक की व्यवस्था की गई।

→ वस्तुत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।

— सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये समाज के अधिक निर्धन वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह नीति अपनाई गई।

(*) खाद्य गोदामों में खाद्यान्नों की अधिकता के कारण

→ (i) MSP के चलते किसान खाद्यान्न फसलों पर अधिक फोकस
[यथा] - गेहूँ-धान प्रणाली का विकास

→ (ii) खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार के कारण लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुँच सीमित

— वस्तुतः वर्तमान बफर स्टॉक प्रणाली मे सुधार की आवश्यकता है।

- (i) बफर स्टॉक में आहार विविधता को बढ़ावा
- (ii) लाभार्थी तक उचित मूल्य में खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करना
- (iii) बफर स्टॉक हेतु खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा सीमित करना
- (iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, रिसाव जैसी प्रवृत्तियों को रोकना
- (v) बफर स्टॉक में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों को बढ़ावा
  (चूँकि निम्न गुणवत्ता के चलते भी लोग इनकी खरीद में रुचि नहीं लेते)

वस्तुतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्नों का वितरण सतत विकास लक्ष्य (SDG) - 2.0 (जीरो हंगर) के अनुकूल है। किन्तु उसका युक्तिसंगत

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

।वितरण सुनिश्चित करने हेतु बफर स्टॉक प्रणाली में सुधार समय की मांग है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. हाल ही में, सरकार ने सभी पत्तनों (पोर्ट्स) को वर्ष 2047 तक स्वयं को 'मेगा पोर्ट्स' के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देश दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में, पत्तनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और साथ ही, भारत की ब्लू इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the government has asked all ports to prepare a master plan in order to become 'mega ports' by 2047. In light of this, discuss the challenges faced by ports and suggest remedial measures in order to propel India's blue economy. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चूँकि भारी माल एवं किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने में यह सहायक है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो।

(*) भारत के प्रमुख बंदरगाह

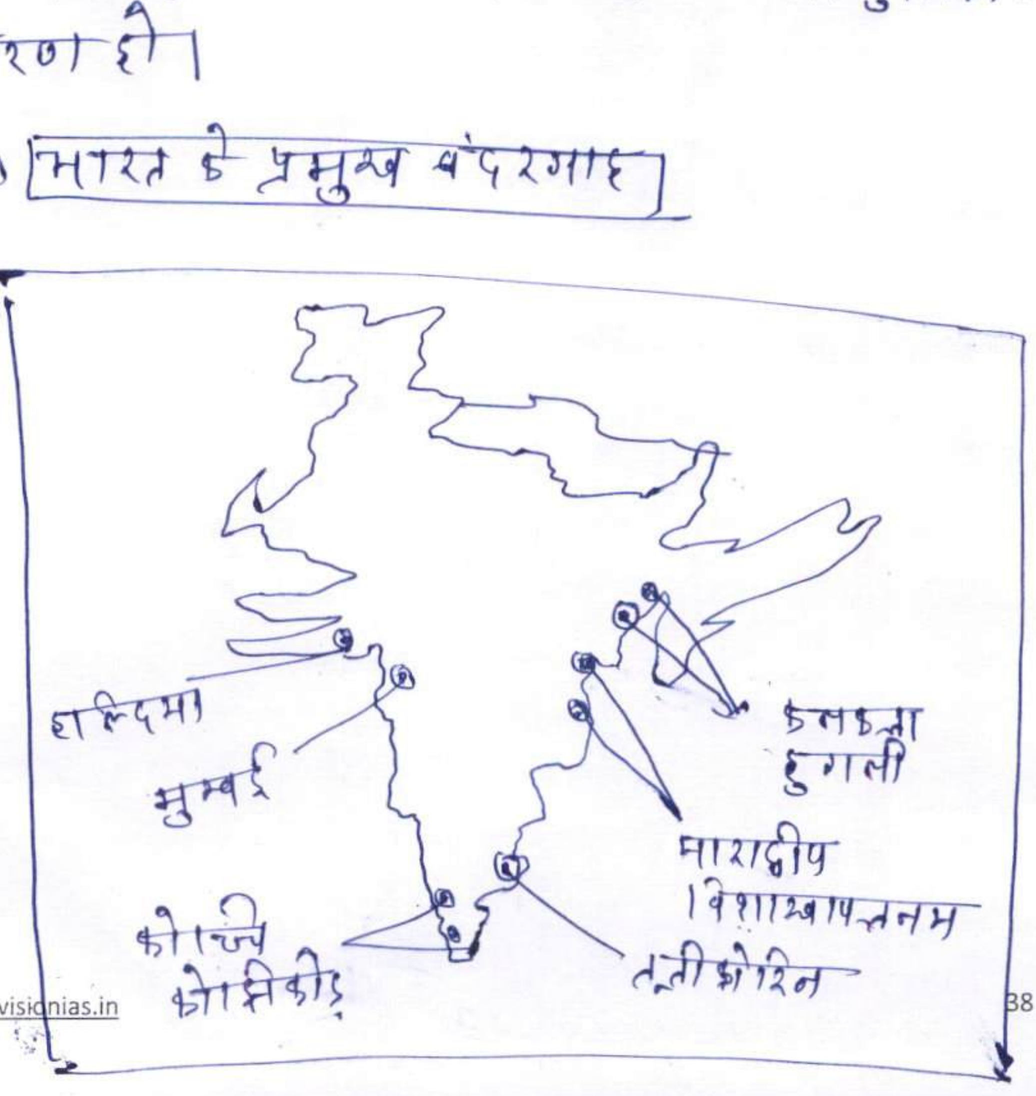

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(क) भारतीय बंदरगाह द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियाँ

- (i) बेहतर अवसंरचनात्मक विकास का अभाव
- (ii) आधुनिक भारवाही पत्तनों का विकास नहीं
- (iii) लॉजिस्टिक लागत अधिक
- (iv) आधुनिक तकनीकों पर आधारित पत्तन नहीं

(ख) भारतीय ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु उपचारात्मक उपाय

- (i) पोर्टस का आधुनिकीकरण
- (ii) उच्च क्षमता वाले पत्तनों का विकास
- (iii) नवीन तकनीकों के विकास हेतु R&D व्यय में वृद्धि
- (iv) द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से बाहरी देशों से नवीन तकनीक हेतु सहयोग

(v) कनेक्टीविटी को बढ़ाने हेतु निवेश में वृद्धि

(vi) मत्तनों को वृहद पत्तनों में रूपांतरित करने हेतु रणनीति

(vii) PPP मोड द्वारा नवीनीकृत

वस्तुतः बिना पत्तनों के आधुनिकीकरण के भारत की ब्लू-इकोनॉमी का विकास संभव नहीं है। अतः पत्तनों के विकास हेतु बेहतर रणनीति समय की मांग है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. आय और संपदा में असमानता कार्बन असमानता में परिवर्तित हो जाती है। इस संदर्भ में, भारत के लिए कार्बन असमानता को दूर करने के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसे प्राप्त करने के उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Inequality in income and wealth translates into carbon inequality. In this context, discuss the significance of addressing carbon inequality for India and suggest ways to achieve it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर – नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे – 4.0 के अनुसार ग्रामीण भारत में लगभग 56% परिवार ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं।

वस्तुतः यह स्थिति निम्नलिखित कारणों का परिणाम है–

(i) यद्यपि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाये, तथापि अपर्याप्त आय के कारण अधिकांश लोग ठोस ईंधन पर अपनी निर्भरता बनाए हुए हैं।

(ii) अपर्याप्त आय के कारण स्वच्छ ईंधन स्त्रोतों तक पहुँच सीमित

विश्व असमानता रिपोर्ट – 2022 के अनुसार → भारत में (50%) आबादी के पास केवल (13%) (राष्ट्रीय GDP का कुल) संपत्ति है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(★) भारत के लिए कार्बन असमानता को दूर करने का (महत्व)

(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अधिकांश महिलाएँ प्रदूषित वायु के कारण फेफड़े संबंधी रोगों से ग्रस्त है।
(ठोस ईंधन पर निर्भरता)

(ii) कार्बन असमानता के चलते नेट जीरो एमीशन टारगेट-2070 की प्राप्ति संभव नहीं

(iii) यदि कार्बन असमानता जारी रहती है तो भारत में बढ़ते तापमान के चलते चरम मौसमी घटनाओं की संख्या भी बढ़ेगी। जिसका दुष्परिणाम सबसे अधिक सुभेद्य वर्ग को होगा

(iv) अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु
[यथा]- 'पंचप्रण' - भारत को विकसित बनाना। 5 ट्रिलियन $. समावेशी विकास हेतु

(*) उपाय — (i) थर्ड डॉप के तौर पर सोलर पैनलों को बढ़ावा

(ii) निर्धनता उन्मूलन हेतु रणनीतिक उपाय जरूरी

(iii) E-व्हिकल्स को बढ़ावा देने हेतु टैक्स प्रोत्साहन

(iv) निर्धन आबादी को सब्सिडी एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा हरित तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित करना।

वस्तुतः कार्बन असमानता समाप्त करने हेतु यह जरूरी है कि देश में निर्धनता उन्मूलन हेतु बेहतर रणनीति अपनाई जाए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. भारत में पिछले एक दशक के दौरान भूस्खलन की बढ़ती और नियमित घटनाओं के बावजूद, विकास के प्रमुख प्रतिमानों (पैरडाइम) में कोई मुख्य संशोधन नहीं किया गया है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite increased and regular occurrences of landslides over the past decade in India, the dominant development paradigm has largely not been modified. Examine. (Answer in 250 words)15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर – भारत विश्व मे भूस्खलन से प्रभावित प्रमुख देश है। वस्तुतः देश का लगभग (12%) भाग भूस्खलन के प्रति सुभेद्य है।

→ भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारण

(I) प्राकृतिक कारण
- (i) अत्याधिक वर्षा
- (ii) भूकम्प एवं ग्लेशियर विवर्तनिकी जैसी घटनाएं
- (iii) बादल फटना
- (iv) कमजोर चट्टाने

(II) मानवीय कारण
- (i) सुभेद्य क्षेत्रों मे अवसंरचनात्मक गतिविधियाँ
  यथा – उत्तराखंड मे
- (ii) बेहतर निरीक्षण के बिना ही पर्वतीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियाँ
- (iii) असंधारणीय पर्यटन
- (iv) वनोन्मूलन

→ वस्तुतः पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन हेतु असंधारणीय विकासात्मक गतिविधियाँ ही कारण रही है।

→ जबकि 'कस्तूरीरंगन समिति' ने पश्चिमी घाट की सुभेद्यता को बतलाया था।

(ख) भूस्खलन के शमन हेतु उपाय

→ गैर संरचनात्मक उपाय

(i) बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली

(ii) सुभेद्य क्षेत्र का मानचित्रण

(iii) विकासात्मक गतिविधियों से पूर्व निरीक्षण

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(*) संरचनात्मक उपाय

(I) हिमालयन क्षेत्र में सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए अवसंरचनात्मक विकास

(II) पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक

(III) पश्चिमी घाट में वनों का अधिकतम रोपण

(IV) सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना

वस्तुतः सेण्डई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भूस्खलन जैसी आपदाओं का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। साथ अवसंरचनात्मक विकास संधारणीय होना चाहिए।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ वैध सीमा-पार प्रवाह को संतुलित करने के लिए भारत को एक स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

India needs a smart border management system to balance legitimate cross border flows with national security interests. Discuss. Also, highlight the initiatives taken by the government in this regard. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर - भारत दुर्गम क्षेत्रों एवं छिद्रिल सीमाओं के कारण सदैव सुरक्षा के चलते बाधाओं का सामना करता रहा है।

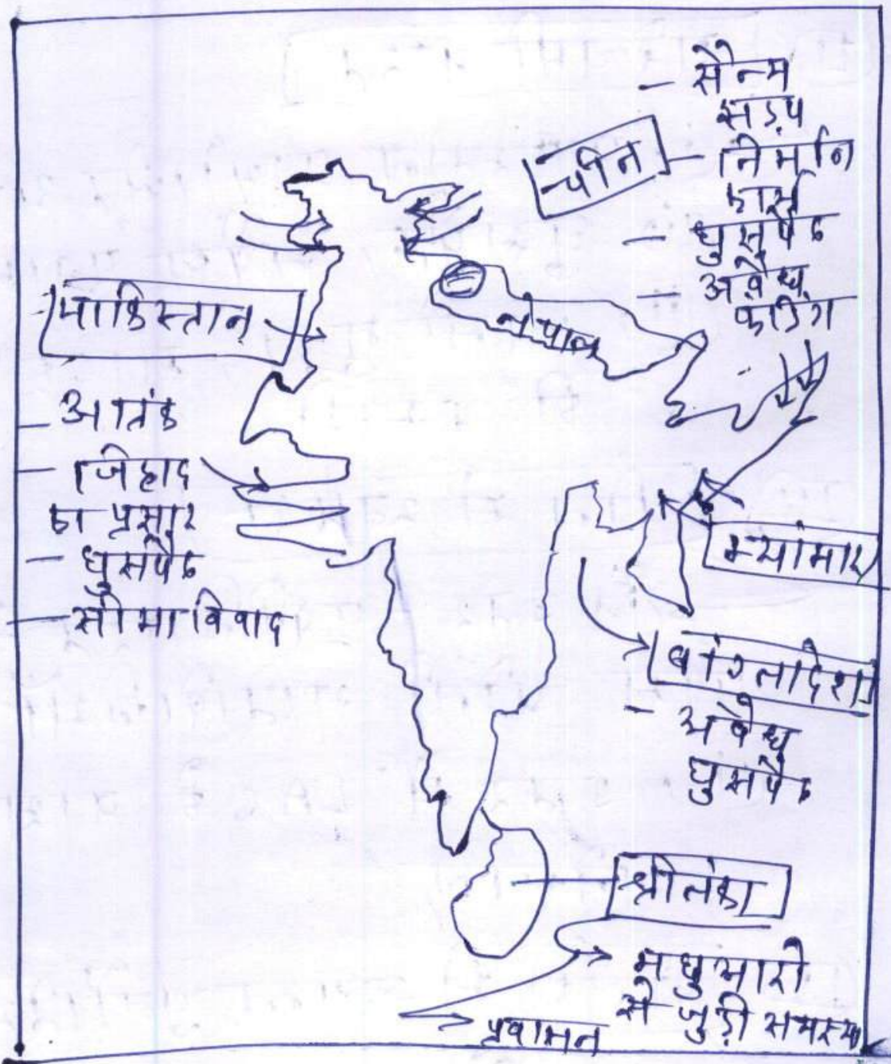

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(*) स्मार्ट बॉर्डर मैकेनिज्म क्यों?

→ (I) उत्तर-पूर्वी भारत में म्यांमार एवं बांग्लादेश से चुनौतियाँ

(i) अवैध घुसपैठ
(ii) मादक पदार्थों, मानव एवं पशु तस्करी
(iii) जाली मुद्रा का प्रसार

(II) पश्चिमी भारत

→ (i) पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद
(ii) घुसपैठ, अवैध प्रवासन
(iii) जाली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी

(III) चीन से खतरा

→ (i) उत्तर-पूर्वी भारत के पास चीनी गतिविधियाँ
(ii) उत्तर में LAC के पास सैन्य निर्माण

(IV) श्रीलंका से उत्पन्न चुनौतियाँ

→ (i) अवैध प्रवासन
(ii) शरणार्थी समस्या

* स्मार्ट बॉर्डर मैकेनिज्म हेतु सरकारी पहल →

(i) BOLD - QIT

→ बेहतर निगरानी हेतु रडार, सेंसर आदि का प्रयोग

→ असम ब्रह्मपुत्र सीमा पर

(ii) बजट - 2022-23 में घोषणा

पी.एम. डिवाइन
→ उत्तर-पूर्व में अवसंरचना विकास

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
→ सैन्य उद्देश्यों से गाँवों का विकास

वस्तुतः वर्तमान संदर्भ में उभरती तकनीक के साथ कई नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई इनसे निपटने हेतु स्मार्ट बॉर्डर मैकेनिज्म उपयुक्त प्रतीत होता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. वैश्वीकरण और धन शोधन के बीच संबंध स्थापित करते हुए, इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Establishing linkages between globalisation and money laundering, discuss the initiatives taken at the national and international levels to combat it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर - धन शोधन से तात्पर्य अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध बनाने की प्रक्रिया।

→ **धनशोधन के तरीके**
- (i) हवाला कारोबार
- (ii) शेल कंपनियों
- (iii) क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आदि

— वस्तुतः वैश्वीकरण के कारण धन शोधन को बढ़ावा मिला है।

यथा – (1) उभरती हुई तकनीकों के चलते अवैध धन को छिपाना एवं वैध धन में बदलना आसान
(ii) स्विस बैंक में विभिन्न राष्ट्रों के बड़े-2 लोगों का अवैध धन संचित

(iii) नवीन क्रिप्टोकरेंसी ने भी धन शोधन की प्रक्रिया को तीव्र किया है।

(*) **धन शोधन के दुष्परिणाम**

- (i) राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता के सम्मुख चुनौती
- (ii) आतंकी फंडिंग
- (iii) राजकोषीय घाटा
- (iv) कर अपवंचन की प्रक्रिया व्यापित

(*) **धन शोधन से निपटने हेतु भारत सरकार की पहल**

(1) PMLA एक्ट - 2002

- अवैध संपत्ति पर नियंत्रण (जब्त करना)
- धन शोधन की प्रक्रिया पर नियंत्रण हेतु

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(ii) ED (प्रवर्तन निदेशालय)

→ FEMA एक्ट – 1999 का क्रियान्वयन

वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धन शोधन पर नियंत्रण हेतु उपाय किए जा रहे हैं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. ऐसे तर्क दिए गए हैं कि भारत को बाह्य अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में अपनी कुछ पुरानी धारणाओं की समीक्षा करने और नए वैश्विक मानदंडों के विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
There have been arguments that India needs to review some of its past assumptions about the nature of outer space and contribute to the development of new global norms. In this context, analyse India's stand in relation to the Artemis Accords. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर – हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में संपन्न आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष क्षेत्र में नई साझेदारी को बढ़ाएगा।

→ प्रमुख उद्देश्य
- (i) अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी
- (ii) अंतरिक्ष में नई संभावनाएँ तलाशना
- (iii) सदस्य राष्ट्रों की अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुँच बढ़ाना
- (iv) अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करना

— वस्तुतः भारत आर्टेमिस समझौते का सदस्य नहीं है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(क) अंतरिक्ष से जुड़ी भारत की परंपरागत धारणाएँ

(i) अंतरिक्ष एक सार्वजनिक/साझा संपत्ति है उसका संरक्षण सभी राष्ट्रों को करना चाहिए

(ii) अंतरिक्ष संधियों के अनुरूप कार्य

(iii) अंतरिक्ष नैतिकता का अनुपालन

(ख) वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी पहलें →

(i) निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहायता एवं प्रोत्साहन

(ii) अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमों की घोषणा

(iii) क्वाड सदस्य, रूस के साथ अंतरिक्ष में सहयोग को महत्व देना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(*) आगे की राह

① भारत को अंतरिक्ष में संभावित अवसरों की तलाश हेतु आर्टेमिस समझौते का हिस्सा बनना चाहिए।

② अंतरिक्ष क्षेत्र में संधारणीयता हेतु पहल करना।

वस्तुतः वर्तमान समय में भारत अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी परंपरागत धारणाओं को पीछे छोड़ रहा है एवं अपने अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।

यथा → मिशन गगनयान

SPACE FOR ROUGH WORK